

1. मुकुट घनश्याम मित्तल पुत्र रामगोपाल
2. अभिषेक मित्तल पुत्र मुकुट घनश्याम मित्तल
जाती महाजन, निवासी छावनी मैन रोड, कोटा

.... प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान जरिये उप पंजीयक कोटा प्रथम

...अप्रार्थी

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित ::

श्री रोहित सोनी

अभिभाषक

श्री अनिल पोखरणा

उप-राजकीय अभिभाषक

....प्रार्थीगण की ओर से

...अप्रार्थी राजस्व की ओर से

निर्णय दिनांक : 24.04.2018

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) कोटा (जिसे आगे 'कलक्टर' कहा गया है) के आदेश दिनांक 03.07.2017 प्रकरण संख्या 86/2015 के विरुद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे 'मुद्रांक अधिनियम' कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने उपपंजीयक कोटा प्रथम द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया गया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मुकुट घनश्याम मित्तल, अभिषेक मित्तल व श्री तरुण मित्तल पिसरान मुकुट घनश्याम मित्तल के मध्य पारिवारिक बटवारा नामा "महावीर ऑयल मिल" सम्पत्ति का दिनांक 14.10.2009 को पंजीयन वास्ते उप पंजीयक कोटा प्रथम के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे उप पंजीयक द्वारा सम्पत्ति की मालियत 25,00,000/- रुपये दस्तावेज बटवारा नामा पंजीयन कर अप्रार्थी को लौटा दिया गया। तत्पश्चात् महालेखाकार निरीक्षक दल द्वारा उक्त बटवारा नामा पर मुद्रांक अधिनियम की धारा 42 के अनुसार एक बड़े भू-भाग को छोड़कर शेष भाग पर कन्वेन्स की दर से मुद्रांक शुल्क नहीं लेने से 2,25,916/- रु. की कर अपवंचना से आक्षेपित किया गया। तत्पश्चात् उप पंजीयक द्वारा मुद्रांक वसूली हेतु प्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। प्रार्थीगण द्वारा राशि जमा नहीं कराने पर उपपंजीयक द्वारा प्रकरण वसूली हेतु अधीनस्थ न्यायालय में प्रेषित किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थीगण को मुद्रांक अधिनियम की धारा 51 (3) राजस्थान स्टाम्प अधिनियम

1998 व सपठित नियम 65 (2) राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 2004 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय ने रेफरेन्स स्वीकार करते हुये मालियत 25,00,000/- रु आकते हुये कमी स्टाम्प 1,15,000/- रु तावान 1,08,100/-रु कुल 2,23,100/- राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये जिसके विरुद्ध राज्य पक्ष की ओर से यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

3. निगरानी दर्ज की जाकर रिकार्ड व अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित आये।

4. बहस विद्वान उप राजकीय अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अप्रार्थी को जिस विभाजन/बंटवारनामा के सम्बन्ध में कमी मुद्रांक की राशि जमा कराने हेतु उक्त नोटिस प्रेषित किया गया है उस विभाजन पत्र से छावनी कोटा स्थित पैतृक सम्पत्ति का प्रार्थी मुकुट घनश्याम मित्तल व उसके पुत्रों अभिषेक मित्तल व वरुण मित्तल के मध्य विभाजन हुआ है। उक्त विभाजन पत्र पर देय मुद्रांक कर अदा करके दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया था, जिसे उप पंजीयक ने तत्समय प्रभावी कानूनी प्रावधान अनुसार पूर्ण संतुष्टी के उपरान्त प्रार्थीगण को पंजीकृत कर लौटा दिया था, उक्त दस्तावेज पर देय मुद्रांक कर अदा किये जाने के पश्चात अन्य कोई राशि देय नहीं है। इस तथ्य को स्वयं रेफरेन्सकर्ता उप पंजीयक भी स्वीकार करते हैं जो पत्रावली पर उपलब्ध ऑडिट आक्षेप में किये गये वर्णन से स्पष्ट है। इस प्रकार उक्त दस्तावेज के संबंध में उप पंजीयक द्वारा रेफरेन्स करने एवं उक्त रेफरेन्स की इस माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार कर अप्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही करने में त्रुटि की है। उक्त विभाजन पत्र वाली सम्पत्ति अप्रार्थी की उसके स्व. पिता एवं उसके पुत्रों अभिषेक मित्त व वरुण मित्तल के स्व. दादा की मृत्यु के पश्चात उनके विधि सम्मत उत्तराधिकारी होने से संयुक्त रूप से स्वामी चले आ रहे थे। उक्त सम्पत्ति को इस विवादित दस्तावेज से सह स्वामियों ने भविष्य की सुरक्षा के मध्यनजर विभाजित किया है। इस प्रकार उक्त दस्तावेज से पैतृक सम्पत्ति का विभाजन किया गया है एवं उस पर कानून/विधि अनुरूप आवश्यक मुद्रांक अदा कर पंजीकृत कराया गया है। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक 09.09.7.98 द्वारा 08.03.16 तक प्रभावी थी। जो वर्तमान में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ4(6)वित्त/कर/2016-17 दिनांक 08.03.16 से प्रमाणित है। इस प्रकार प्रस्तुत कार्यवाही त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। राज्य सरकार के वित्त विभाग के परिपत्र प.2(50)वित्त/कर/2010 दिनांक 01.12.10 द्वारा स्टाम्प अधिनियम 1998 के लागू होने की दिनांक 27.05.04 से पूर्व जारी अधिसूचनाओं के सम्बन्ध में मार्गदर्शन बाबत जारी किया है। जिसके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि पूर्व अधिनियम में स्टाम्प

ड्यूटी को कम किये जाने व छूट दिये जाने की शक्तियाँ कम थी तथा वर्तमान नये अधिनियम में भी धारा 9 के अधीन राज्य सरकार को इस प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त है अतः स्टाम्प मुद्रांक अधिनियम की धारा 51 के तहत रेफरेन्स किया जो पूर्णतः गलत है। धारा 51 में मालियत का निर्धारण किया जाता है। यह धारा इस प्रकरण पर लागू नहीं होती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है।

6. विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की धारा 2 (xx) में विभाजन-पत्र (Partition Deed) को परिभाषित किया गया है। अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल-42 के अनुसार विभाजन पत्र पर सम्पत्ति के एक सबसे बड़े हिस्से को छोड़कर शेष अलग हुये हिस्से/हिस्सों पर कन्वेन्स की दर से मुद्रांक कर प्रभाय है। प्रश्नगत दस्तावेज के द्वारा विभाजन-पत्र के माध्यम से अचल सम्पत्ति विभिन्न बटवाराकर्ताओं के मध्य विभाजन किया गया है जिसमें सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा स्वामित्व एवं अधिकार हस्तान्तरित हुआ है। अतः उक्त आर्टिकल-42 की अनुपालना करते हुये कन्वेन्स की दर से मुद्रांक कर प्रभाय है जिसके आधार पर प्रस्तुत रेफरेन्स का स्वीकार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है। अतः निगरानी अस्वीकार की जावे।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :-

8. अधीनस्थ न्यायालय में रेफरेन्स का मुख्य आधार यह था कि राजस्थान मुद्रांक अधिनियम के आर्टिकल-42 के अनुसार विभाजन पत्र के दस्तावेज में संपत्ति के एक बड़े हिस्से को छोड़ते हुये शेष हिस्से की मालियत पर कन्वेन्स की दर से मुद्रांक कर देय होना चाहिए। अप्रार्थी ने राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 संख्या एफ4(14)एफडी/डिवी/98-52 के अनुसार पैतृक संपत्ति के बटवारा नामा पर एक बड़े हिस्से को छोड़कर शेष हिस्सों की मालियत पर 1 प्रतिशत अधिकतम रु. 10,000/- मुद्रांक कर लिये जाने की रियायत होने की बात कही है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेफरेन्स इस आधार पर स्वीकार किया है कि उक्त अधिसूचनाएँ अधिनियम की धारा 92(2) संपत्ति शेड्यूल के आर्टिकल के असंगत है जिससे छूट का लाभ देय नहीं है।

9. प्रकरण में इस बिन्दु पर विचार किया जाता है कि उपरोक्त अधिसूचना जो भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 जो कि वर्तमान राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के लागू होने की दिनांक 27.05.2004 से पूर्व लागू था, के अन्तर्गत जारी अधिसूचना वर्तमान अधिनियम के असंगत है या नहीं तथा इसका लाभ इस दस्तावेज पंजीयन दिनांक 14.10.2009 पर देय है या नहीं। इस संबंध में राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा 91 (2) का अवलोकन किया जाता है जो निम्न प्रकार है :-

अ

91. Repeal and Savings —

(2) Any appointment, notification, notice, order, rule or form made or issued under the enactment hereby repealed shall be deemed to have been made or issued under the provisions of this Act, in so far as such appointment, notification, notice, order, rule or form is not inconsistent with the provisions of this Act and shall continue in force, unless and until it is superseded by an appointment, notification, notice, order, rule or form made or issued under this Act. इस प्रावधान से यह स्पष्ट है कि पुराने अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गई कोई अधिसूचना नये अधिनियम में तब तक लागू होगी जब तक कि यह अधिसूचना अतिष्ठित (Superseded) न कर दी जावे। अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 को प्रत्याहारित करने के संबंध में राज्य पक्ष की ओर से कोई परिपत्र या अधिसूचना या विधिक प्रावधान प्रस्तुत नहीं किया है। राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की धारा 9 (1) निम्न प्रकार है :-

9 - Power to reduce, remit or compound duties

(1) The Government, if satisfied that it is necessary to do so in the public interest, may by rule or order published in Official Gazette, reduce or remit, whether prospectively or retrospectively, in the whole or any part of the territories under its administration, the duties with which any instruments or any particular class of instruments, or any of the instruments belonging to such class, or any instruments when executed by or in favour of any particular class of persons, or by or in favour of any member of such class are chargeable. इस प्रावधान के अन्तर्गत राज्य सरकार को जनहित में शुल्क को कम करने की शक्तियाँ प्रदत्त है। अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 की धारा 9 के अन्तर्गत जारी की गई है जिसमें भी राज्य सरकार को शुल्क कम करने की शक्तियाँ थी। इस प्रकार जिन शक्तियों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 की धारा 9 के अन्तर्गत शुल्क में रियायत की अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 जारी की गई है, वही शक्तियाँ राज्य सरकार को राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की धारा 9 के अन्तर्गत प्रदत्त है तथा यह अधिसूचना नये अधिनियम के अन्तर्गत असंगत नहीं मानी जा सकती।

इस संबंध में मुद्रांक विभाग द्वारा ली गई विधिक स्थिति हेतु महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर का परिपत्र संख्या 24/2015 क्रमांक : एफ 7(39)जन/मार्गदर्शिका/2015/पार्ट/4671 दिनांक 17.06.2015 अवलोकनीय है जो निम्नुसार है :- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के लागू होने की दिनांक 27.05.2004 से पूर्व लागू राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत दी गई मुद्रांक शुल्क की रियायतें वर्तमान में प्रभावी होने के संबंध में :-

“राज्य सरकार द्वारा पत्र क्रमांक. प.2(50)वित/कर/10 दिनांक 01.12.2010 द्वारा विधि विभाग की राय के आधार पर यह स्पष्ट किया है कि राज. स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा 91(2) के अनुसार राजस्थान स्टाम्प लॉ (अडपटेशन) एक्ट, 1952 (भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899) के प्रावधानों के अधीन जारी अधिसूचनायें नये अधिनियम में भी जारी की गई समझी जावेगी, जब तक की वे वर्तमान अधिनियम, 1998 के प्रावधानों से असंगत न हों। पूर्व अधिनियम में स्टाम्प शुल्क को कम करने की शक्तियां राज्य सरकार को थी, तथा नये अधिनियम की धारा 7 में भी ये शक्तियां राज्य सरकार को प्राप्त हैं। राज्य सरकार के उद्देश्योक्त मार्गदर्शन से यह स्पष्ट है कि पूर्व अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क में रियायत के संबंध में जारी समस्त अधिसूचनाएँ वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत भी प्रभावी हैं।”

विभाग स्वयं द्वारा ली गयीं उपरोक्त विधिक धारणा से भी स्पष्ट है कि मुद्रांक शुल्क में रियायत के संबंध में जारी समस्त अधिसूचनाएँ वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत भी प्रभावी हैं। इस प्रकार इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 जो भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 जो कि वर्तमान राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के लागू होने की दिनांक 27.05.2004 से पूर्व लागू था, के अन्तर्गत जारी अधिसूचना का लाभ इस दस्तावेज पंजीयन दिनांक 14.10.2009 पर देय है।

10. प्रकरण में इस बिन्दु पर भी विचार किया जाता है कि जिस संपत्ति का विभाजन पत्र निष्पादित किया गया था वह संपत्ति पैतृक है या नहीं। पैतृक संपत्ति के संबंध में The Advanced Law Lexicon (Law Dictionary compiled and edited by P. Ramanatha Aiyar Published by Wadhwa & Company Nagpur, India 3rd Edition Reprint 2007) में निम्न प्रकार उल्लेख किया गया है :— **Ancestral Property : If property came to a son as gift from his father; it can not be regarded his ancestral property. Ancestral properties in the ordinary sense mean property of the father which is inherited. Ancestral property does not necessarily mean property which has been a long time in a family, it rather means, property derived from the proprietor's father.** इस डिक्शनरी में पैतृक संपत्ति के संबंध में की गई व्याख्या से यह स्पष्ट है कि यदि कोई संपत्ति पिता या उच्चतर श्रेणी के पूर्वजों से कोई संपत्ति प्राप्त होती है तो वह पैतृक संपत्ति की श्रेणी में है।

बंटवारनामा दस्तावेज पंजीयन दिनांक 14.10.2009 में बंटवारनामा श्री मुकुट घनश्याम मित्तल पुत्र श्री रामगोपाल, श्री अभिषेक मित्तल पुत्र श्री मुकुट घनश्याम मित्तल एवं श्री तरुण मित्तल पुत्र श्री मुकुट घनश्याम मित्तल के मध्य निष्पादित हुआ है। दस्तावेज के पृष्ठ संख्या 1 पर यह उल्लेख किया गया है कि सम्पूर्ण सम्पत्ति मुकिए

2012

नम्बर 1 श्री मुकुट घनश्याम मित्तल के स्व. पिता व मुकिर नं. 2 व 3 के स्व. दादा श्री रामगोपाल जी ने निजामत रामचन्द्रपुरा तहसील लाड़पुरा से क्रय की थी जिसका विक्रय की स्वीकृति दिनांक 29.0.1938 को जारी की गई थी। इस प्रकार संपत्ति श्री रामगोपाल की स्व-अर्जित संपत्ति है जो उनके पुत्र श्री मुकुट घनश्याम मित्तल व पौत्र श्री अभिषेक मित्तल व तरुण मित्तल को श्री रामगोपाल से विरासतन प्राप्त हुई है जो उनकी पैतृक संपत्ति मानी जायेगी। इस प्रकार निगरानी का यह आधार स्वीकार योग्य नहीं है कि बंटवारनामा से संबंधित संपत्ति पैतृक नहीं है।

11. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर बंटवारनामा से संबंधित संपत्ति श्री रामगोपाल की स्व-अर्जित संपत्ति है जो उनके पुत्र श्री मुकुट घनश्याम मित्तल व पौत्र श्री अभिषेक मित्तल व तरुण मित्तल को विरासतन प्राप्त हुई है जो उनकी पैतृक संपत्ति मानी जायेगी। संपत्ति विरासतन प्राप्त होने के कारण पैतृक एवं ऐसे दस्तावेज पर अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 लागू होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर निगराधीन निर्णय निरस्त किया जाता है।

12. निर्णय सुनाया गया।

(नटथूराम)
सदस्य